



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]  
No. 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISHAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

रक्षा मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

का.नि.सं. 4(प्र).—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उपधारा (2) के खंड (क), (घ), (ङ) (च), (ट) और (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक (संघारण) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) अभिप्रेत है,

(ख) "उपनिषद्" से इन नियमों से सम्बन्धित अधिसूचना है,

(ग) "बोर्ड" से नियम 36 के अधीन संयोजित जांच बोर्ड अभिप्रेत है,

(घ) "तटरक्षक आदेश" से तटरक्षक महानिदेशक द्वारा जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है,

(ङ) "तटरक्षक क्षेत्र" से नियम 4 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कोई तटरक्षक क्षेत्र अभिप्रेत है,

(च) "कार्यपालक अधिकारी" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो पोत के कार्यपालक कर्तव्यों का निष्पादन करता है,

(छ) "क्षेत्रीय कमान्डर" से नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट कमान्डर तटरक्षक क्षेत्र, अभिप्रेत है,

(ज) उन प्रावदों और पर्वों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. रिपोर्ट और आवेदन:— इन नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी तटरक्षक प्राधिकारी को को जाने वाली कोई रिपोर्ट या आवेदन, उचित प्रणाली के माध्यम से लिखित रूप में किया जाएगा, जब तक कि उक्त प्राधिकारी सेवाओं की अत्यावश्यकताओं के कारण या अन्यथा लेखन से अभिसृजित न दे दे।

## अध्याय 2

## संगठन

4. तटरक्षक का गठन—(1) तटरक्षक में अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, नाविक और तटरक्षक सेवा में नियुक्त या अध्यावेशित अन्य अध्यावेशित व्यक्ति होंगे।

(2) महानिदेशक निम्नलिखित प्राधिकारियों के माध्यम से समावेशन करेगा—

- (क) कमांडर, तटरक्षक, क्षेत्र, पश्चिम,
- (ख) कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र, पूर्व
- (ग) कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र, अध्यावेशन और निकोबार द्वीप, और
- (घ) कमांडर, तटरक्षक सीमा-शुल्क

(3) (क) तटरक्षक क्षेत्र, पश्चिम में तटीय क्षेत्र और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्यों और गोवा, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के सामुद्रिक क्षेत्र समाविष्ट होंगे,

(ख) तटरक्षक क्षेत्र, पूर्व में तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों और पाँचवरी संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के सामुद्रिक क्षेत्र समाविष्ट होंगे,

(ग) तटरक्षक क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप, में तटीय क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ सामुद्रिक क्षेत्र समाविष्ट होंगे।

(घ) कमांडर, तटरक्षक सीमा-शुल्क, महानिदेशक द्वारा उसे सौंपे गए सभी पोतों पर सक्रियात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण करेगा।

5. प्रत्येक तटरक्षक क्षेत्र को जिलों में भी विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक जिला महानिदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिला कमांडर के पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

6. महानिदेशक, समय-समय पर सेवा की आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए, उक्त संख्या में स्टेशन स्थापित करेगा और उक्त संख्या में पीछे पथ्येक तटरक्षक क्षेत्र/जिला/स्टेशन को सौंपेगा जितना वह उचित समझे।

9. विशेषज्ञता—अधिकारी और अध्यावेशित व्यक्ति निम्नलिखित रूप में विशेषज्ञता के पात्र होंगे, अर्थातः—

कार्य के प्रकार	विशेषज्ञता	अथवा विशेषज्ञता
(क) (1) अधिकारी (साधारण कर्तव्य)	पाइलट नौधालक विधि प्रदूषण नियंत्रण उद्धारण पोशाखी	अथवा विशेषज्ञता लागू नहीं होता
(2) अधिकारी (तकनीकी)	विमानन इंजीनियरी विद्युत इंजीनियरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी प्रदूषण नियंत्रण उद्धारण ती-वास्तुकला समुद्री इंजीनियरी	लागू नहीं होता

## अध्याय-3

## रैंक और समावेशन

7. वर्गीकरण और रैंक—तटरक्षक के अधिकारियों और अन्य सदस्यों का वर्गीकरण उनके रैंकों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों में किया जाएगा, अर्थातः—

(क) अधिकारी—

- (1) महानिदेशक
- (2) महानिरीक्षक
- (3) उपमहानिरीक्षक
- (4) कमांडेंट,
- (5) उप कमांडेंट
- (6) सहायक कमांडेंट

(ख) अधीनस्थ अधिकारी—

- (1) प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर,
- (2) उत्तम अधिकारी/उत्तम सहायक इंजीनियर,
- (3) अधिकारी/सहायक इंजीनियर।

(ग) नाविक—

- (1) प्रधान नाविक/प्रधान यांत्रिक,
- (2) उत्तम नाविक/उत्तम यांत्रिक,
- (3) नाविक/यांत्रिक।
- (घ) अध्यावेशित अनुचर।

8. शाखाएं—(1) वे शाखाएं, जिनमें अधिकारियों का वर्गीकरण किया गया है, निम्नलिखित होंगी—

- (क) साधारण कर्तव्य
- (ख) तकनीकी।

(2) वे शाखाएं, जिनमें अध्यावेशित व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है, निम्नलिखित होंगी—

- (क) साधारण कर्तव्य,
- (ख) तकनीकी,
- (ग) प्राकृतिक,
- (घ) अध्यावेशित अनुचर।

(ख) (1) अधीनस्थ अधिकारी और नाविक (साधारण कर्तव्य)	नाविक	(1) तोपखी भेट क्वार्टर मास्टर रेडियो ऑपरटर वायुसैनिक गोताखोर इंजीनियरी वायु इंजीनियरी विद्युत वायु विद्युत वायु रेडियो
	मैकेनिक	
(2) अधीनस्थ अधिकारी और नाविक (सकनाकी)	समुद्री इंजीनियरी वायु इंजीनियरी विद्युत इंजीनियरी वायु विद्युत इंजीनियरी इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी वायु इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी हल इंजीनियरी	लागू नहीं होता
(3) अधीनस्थ अधिकारी और नाविक (आन्तरिक)	पूजित महात्मक रसोइया मनुष्य	लागू नहीं होता

10. तटरक्षक पोतों का समावेशन—(1) तटरक्षक पोतों, जलयान वायुयानों या ऐसे स्थापनों के, जो महानिदेशक द्वारा प्रख्यापित किए जाएं, समावेशन को तकियारमक समावेशन समझा जाएगा।

(2) साधारणतः साधारण कर्तव्य शाखा के अधिकारी या अस्था-  
वैशित व्यक्ति, सक्रियतामक समावेशन करेगा या किसी ऐसे कार्य या  
उपक्रम को निरूपित करेगा जिसमें तटरक्षक सेवा की विभिन्न शाखाओं  
का सहयोग अपेक्षित है। इसे अन्य अधिकारियों और अस्थावैशित  
व्यक्तियों की महानिदेशक द्वारा नियुक्ति या निदेश द्वारा प्रदत्त किया जा  
सकेगा।

(3) पोतों/जलयानों/वायुयान का समावेशन, साधारण कर्तव्य शाखा  
के अर्हित अधिकारियों और नाविक विशेषज्ञता वाले अस्थावैशित व्यक्तियों  
तक सीमित रहेगा, सिवाय तब के जब उसे वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा  
योग्यता और अनुभव द्वारा अर्हित अन्य व्यक्तियों को प्रवृत्त किया जाए।

(4) तटरक्षक पोतों/जलयानों, स्थापनाओं और वायुयानों का समा-  
वेशन तटरक्षक के लिए तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारियों  
और नाविकों द्वारा भी, जब उन्हें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट नियुक्त  
किया जाए, किया जाएगा।

(5) तट स्थानों के समावेशन में नियुक्त तकनीकी अधिकारी,  
समावेशन के ऐसे कृत्य कर सकेंगे जो उनके कर्तव्यों के समुचित पालन के  
लिए आवश्यक हों।

(6) सरकार के नागरिक विभागों के अधीन नियुक्तियां करने वाले  
अधिकारी, महानिदेशक के स्पष्ट आदेशों के बिना, उनके संबंधित विभागों  
में उनके अधीन सेवा कर रहे अधिकारियों और अस्थावैशित व्यक्तियों  
से जिस तटरक्षक के कामकाज पर कोई समावेशन नहीं करेंगे या उन्हें  
कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

11. समावेश करने वाला अधिकारी—रैंक और श्रेणी—तटरक्षक  
पोतों को समावेश करने वाले अधिकारी, सभी श्रेणियों पर, चाहे वे तट  
पर हों या जल पर, उनके समावेशन के अधीन रखे गए अधिकारियों के  
ऊपर रैंक और श्रेणी लेंगे।

12. कमान अधिकारी को अस्थाई अनुपस्थिति में समावेशन—किसी  
तट स्थापन को छोड़कर, (स्टाफ या विशेष कार्य के लिए अतिरिक्त रूप में

नियुक्ति किसी अधिकारी या किसी ऐसे अधिकारी या पोत जलयानों  
का समावेशन करने के लिए अर्हित नहीं है, से जिस कलक पर उद्देश्य  
साधारण कर्तव्य अधिकारी, कमान अधिकारी को अस्थाई अनुपस्थिति में,  
कमान अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य धारण करेगा। किसी तट  
स्थापन, में समावेशन, कमान अधिकारी की शाखा की प्राप्त हो जाएगा।  
यदि कमान अधिकारी को शाखा का कोई अधिकारी उपस्थित न ही हो,  
समावेशन, उपस्थिति उद्देश्य अधिकारी को स्वागत हो जाएगा, किन्तु  
समावेशन, स्टाफ या विशेष कार्य के लिए या चर्याओं के लिए अतिरिक्त  
रूप में नियुक्त किसी अधिकारी को स्वागत नहीं होगा।

13. नियंत्रणी-अधिकारी का प्राधिकार—उप महानिरीक्षक के रैंक  
से नीचे का प्रत्येक अधिकारी (जो तत्समय पोत का कार्यवाहक अधिकारी  
या कमान अधिकारी नहीं है) और अस्थावैशित व्यक्ति, उन कर्तव्यों,  
जिनका भारसाधन उस पर है, के पालन के संबंध में, नियंत्रणी अधिकारी  
के बाह्य, उसका रैंक कोई भी हो, अधिनस्थ होगा।

14. किस प्रकार अधिकारी और अस्थावैशित व्यक्ति धारित होंगे—

(1) जल या तट पर सेवा कर रहे अधिकारी या अस्थावैशित  
व्यक्ति, उस पोत या स्थापन या स्टेशन की, जिसमें वे सेवा कर रहे हैं  
या जिससे वे संलग्न हैं, पुस्तकों में बंधे हुए होंगे।

(2) जब ऐसा जाह्रा गया है कि स्टाफ या विशेष कार्य के लिये  
अतिरिक्त रूप में धारित किसी अधिकारी को, पोत संभालने, और उसी  
प्रकार के कार्य में अस्थायी या अनुभव प्राप्त करना चाहिये तो उसे  
समुद्र या बंदरगाह में निगरानी का भारसाधन ग्रहण करने का प्राधिकार  
कमान अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा : परन्तु इस नियम की कोई भी  
बात, उसे समावेशन के उत्तराधिकार की पवित्र में नहीं रखेगी।

15. प्रोन्नत किया गया अधिकारी—कोई ऐसा अधिकारी, जिसे  
प्रोन्नत किया गया है पूर्ण कर्तव्य जिन्हें उसे सौंपा गया है, का पालन  
करता रहेगा, और वह केवल उस वृत्ति में रैंक और नये रैंकों का समावेशन  
ग्रहण करेगा जब उसकी उच्चतर रैंक में उसके पोत पर पुनर्नियुक्ति की  
जाये।

16. प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी—सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य  
पोत के कलक पर कर्तव्य करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी,  
जहाँ वे अधिनस्थ के रूप में धारित हैं, वही रैंक और समावेशन ग्रहण

करेंगे, तथा वे जिस प्रकार नियोजित हैं उस समय के लिये प्रत्येक बावत वही समझे जायेंगे, मानो वे वस्तुतः कर्म-मण्डल के थे।

17. यात्रा करने वाले अधिकारी—किसी तटरक्षक पोत में यात्रा करने वाले किसी अधिकारी को, यद्यपि वह अधिसंख्य के रूप में धारित है, उस दशा में कर्तव्य करने के लिये आदेश दिया जा सकेगा, यदि वह उस पोत, जिस पर वह बढ़ा हुआ है, के कार्यपालक अधिकारी के रैंक से ऊपर या कनिष्ठ रैंक का है। इस प्रकार नियोजित के दौरान वह वही रैंक और समादेशन ग्रहण करेगा, तथा प्रत्येक बावत यह समझा जायेगा मानो वह वस्तुतः कर्म-मण्डल का था। पोत के कमान अधिकारी की मृत्यु की दशा में, उसका कार्यकारी समादेशन नियम 12 में वर्णित अधिकारियों में निहित हो जायेगा और महानिदेशक के स्पष्ट प्राधिकार के सिवाय किसी भी दशा में किसी अधिसंख्य अधिकारी द्वारा धारण नहीं किया जायेगा।

18. सेना, नौसेना, और वायु सेना के अधिकारियों का प्राधिकार—तटरक्षक पर नियुक्त सेना, नौसेना और वायुसेना के किसी अधिकारी को ऐसी सब शक्तियाँ होंगी और वह ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग करेगा जो तत्समान रैंक के या तत्समान नियुक्ति धारण करने वाले तटरक्षक के किसी अधिकारी में निहित होती हैं या उसके द्वारा प्रयोग की जायें।

19. अधिनियम की धारा 57 और धारा 58 के उपबन्धों को अधीन रहते हुए, जब अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी निकाय से संलग्न किया जाता है, या वह किसी यूनिट में सेवा कर रहा है, या उस नियमित सेवा, नौसेना या वायुसेना के किसी अस्पताल में रोगी के रूप में दाखिल किया जाता है तो ऐसे निकाय, यूनिट या अस्पताल का कमान अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर, जो रैंक में उससे कनिष्ठ हैं, समादेशन की सभी शक्तियों का और अभ्यावेशित कामिक पर समादेशन और बण्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

#### सारणी

संज्ञक प्राधिकारी	तटरक्षक का सबन्ध	आधार जिन पर सेवा समाप्त की जा सकती है	सेवा की समाप्ति के लिए प्रक्रिया
1	2	3	4
केन्द्र सरकार	अधिकारी	(1) अवधार (2) अनुपयुक्तता (3) प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति (4) भर्ती के समय मिथ्या/गलत जानकारी देना (5) अस्वस्थता के आधार पर अयोग्यता (6) अपने अनुरोध पर	नियम 22 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नियम 22 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 25 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 26 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 27 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार।
महानिरीक्षण	अधीनस्थ अधिकारी और नाविक	(1) अवधार (2) अनुपयुक्तता (3) शिक्षण के दौरान असंतोषप्रद प्रगति (4) भर्ती के समय मिथ्या/गलत जानकारी देना (5) अस्वस्थता के आधार पर अयोग्यता (6) अपने अनुरोध पर	नियम 23 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 23 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 25 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 26 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 27 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार।

22. अधिकारियों की पदभ्युति/सेवा से हटाये जाने की प्रक्रिया—

(1) जब किसी अधिकारी की धारा 11 के अधीन पदभ्युत करने/सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव किया गया है तो उसे उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से हेतुक वर्णित करने का अवसर दिया जायेगा।

परन्तु यह उपनियम नहीं लागू रहा होगा—

(क) जहाँ अधिकारी को ऐसे अवधार के आधार पर पदभ्युत/किया गया सेवा से हटाया गया है जिस पर बण्ड न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि की गई है।

(ख) जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, अधिकारी को हेतुक वर्णित करने का अवसर देना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

#### अध्याय 4

सेवानिवृत्ति, पदभ्युति, सेवा से हटाया जाना, सेवानुक्ति या सेवा से निर्मुक्ति

20. सेवानिवृत्ति (1) कमांडेंट के रैंक से उच्चतर कोई रैंक धारण करने वाले अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति की प्राप्ति छठावन वर्ष होगी और अन्य रैंकों के अधिकारियों के लिये यह पचपन वर्ष होगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार—

(क) कमांडेंट के रैंक से उच्चतर रैंक के किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति प्राप्ति किसी भी समय एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में साठ वर्ष की प्राप्ति से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी,

(ख) अन्य रैंकों के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति-प्राप्ति किसी भी समय एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में छठावन वर्ष की प्राप्ति से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी।

(2) अधीनस्थ अधिकारियों और नाविकों की सेवानिवृत्ति-प्राप्ति पचपन वर्ष होगी।

21. पदभ्युति, सेवा से हटाया जाना, सेवानुक्ति या सेवा में निर्मुक्ति

(1) स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट तटरक्षक के सदस्यों की पदभ्युति, सेवा से हटाये जाना, सेवानुक्ति या सेवा से निर्मुक्ति को, इससे उपायबद्ध सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विवरणित आधारों पर, प्राधिकृत करने के लिये सक्षम होंगे। इस नियम द्वारा पूर्वोक्त प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का उससे बरिष्ठ किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) जब, अधिकारी के अवधार की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, महानिरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि किसी तटरक्षक न्यायालय द्वारा अधिकारी का बिचारण समीचीन या साध्य नहीं है और उसकी यह राय है कि अधिकारी को सेवा में और रखना बांछनीय नहीं है, तो महानिरीक्षक, अधिकारी को उसके प्रतिबल सभी रिपोर्टों के साथ इस प्रकार सूचित करेगा और उससे उसका स्पष्टीकरण तथा प्रतिवाद लिखित रूप में प्रस्तुत करने की मांग की जायेगी।

परन्तु महानिरीक्षक, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं ऐसी रिपोर्टों या उनके भाग को प्रकट करने से उस दशा में रोक सकेगा, यदि उसका प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(3) महानिरीक्षक द्वारा अधिकारी के स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझे जाने की दशा में, या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किंवा

जाये, तब मामले को, अधिकारी के प्रतिवाद और अधिकारी की सेवा समाप्त करने के बारे में महानिदेशक की सिफारिश सहित, उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रीति से सरकार के पास प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) जहाँ, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी की बोध-सिद्धि पर, केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक यह समझता है कि अधिकारी के उस आचरण से, सेवा में उसे और रखना अवांछनीय हो गया है जिस पर उसकी बोधसिद्धि की गई है, वहाँ उसे बोधसिद्धि करने वाले दण्ड न्यायालय के निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, अधिकारी की सेवा की समाप्ति के बारे में महानिदेशक की सिफारिश सहित, उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रीति से केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत की जायेगी।

(5) जब उपनियम (3) या (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास कोई मामला प्रस्तुत किया जाये, तब महानिदेशक अपनी यह सिफारिश करेगा कि क्या अधिकारी की सेवा समाप्त की जाये और यदि हाँ तो, क्या अधिकारी को—

(क) पदच्युत कर दिया जाये; या

(ख) सेवा से हटा दिया जाये।

(6) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्टों और यथास्थिति, अधिकारी के प्रतिवाद, यदि कोई हो, या दण्ड न्यायालय के निर्णय और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, अधिकारी को पदच्युत कर सकेगी या सेवा से हटा सकेगी।

(7) जब महानिदेशक का यह समाधान हो गया है कि कोई अधिकारी अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा में रखे जाने के लिये अयोग्य है, तो वह अधिकारी को अपना मामला स्पष्ट करने का अवसर देने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश कर सकेगा कि अधिकारी की सेवा समाप्त की जाये। महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशों के लिये कारण और अधिकारी की सेवा का अभिलेख भी भेजेगा।

परन्तु जहाँ राज्य की सुरक्षा के हित में, अधिकारी को अपना मामला स्पष्ट करने का अवसर देना असंभव हो जाये, वहाँ केन्द्रीय सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह, अधिकारी को अपना मामला स्पष्ट करने का अवसर दिये बिना, अधिकारी की सेवा समाप्त करने का आदेश पारित करे।

(8) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (7) के अधीन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, अधिकारी को पदच्युत करने या सेवा से हटाये जाने का ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(9) केन्द्रीय सरकार, उपयुक्त मामलों में, अधिकारी को पेंशन या उपदान सहित या उसके बिना, सेवा निवृत्त कर सकेगी या सेवा से हटा सकेगी।

23. अध्यावेशित व्यक्तियों को पदच्युत करने, सेवा से हटाये जाने की प्रक्रिया—

(1) जहाँ कमाव अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी अध्यावेशित व्यक्ति को, व्यवहार या अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा में रखे रहना अनुपयुक्त समझा गया है, वहाँ वह, तटरक्षक मुख्यालय में महानिरीक्षक को तटरक्षक से ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने/सेवा से हटाये जाने की सिफारिश कर सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति को पदच्युत करने/सेवा से हटाये जाने की सिफारिश के सभी मामलों में, कमान अधिकारी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि व्यक्ति को उपयुक्त चेतावनी और सुधारने के लिये पर्याप्त समय दिया गया है। सिफारिश के साथ इस आशय का वस्तावेजो साक्ष्य होगा।

(3) जहाँ, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सिद्धांश ठहराये जाने पर, वह उप महानिरीक्षक, जिसके अधीन वह व्यक्ति सेवा कर रहा है, यह समझता है कि व्यक्ति के ऐसे आचरण से, जिसके आधार पर उसे सिद्धांश ठहराया गया है, उसे सेवा में और रखे रहना

अवांछनीय है, वहाँ दण्ड न्यायालय के उसे बोधसिद्धि करने वाले निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, उस उपमहानिरीक्षक के, जिसके अधीन वह व्यक्ति सेवा कर रहा है, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से व्यक्ति की सेवा समाप्त करने से संबंधित सिफारिशों के साथ तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(4) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, उपनियम (1) या (3) के अधीन किसी सिफारिश के प्राप्त होने पर, संबंधित व्यक्ति को पदच्युत करने या सेवा से हटाये जाने का आदेश पारित कर सकेगा।

(5) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, उपयुक्त मामलों में, व्यक्ति को, पेंशन या उपदान सहित या उसके बिना, सेवा निवृत्त कर सकेगा या सेवा से हटा सकेगा।

24. प्रशिक्षण में अंतर्भावप्रद प्रगति के आधार पर सेवान्युक्त/सेवा से निवृत्त की प्रक्रिया—(1) जब तटरक्षक के किसी सदस्य को प्रशिक्षण में अंतर्भावप्रद प्रगति के कारण सेवान्युक्त/सेवा से निवृत्त करने का प्रस्ताव है, तो उस प्रशिक्षण स्थापन का, जहाँ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, कमान अधिकारी यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को, व्यक्ति की सेवान्युक्त या सेवा से निवृत्त के लिए सिफारिश कर सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति को सेवान्युक्त या सेवा से निवृत्त के लिए की गई सिफारिशों के सभी मामलों में, प्रशिक्षण स्थापन का कमान अधिकारी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि व्यक्ति को उपयुक्त चेतावनी और प्रगति दिखाने का पर्याप्त समय दिया गया है। सिफारिश के साथ इस आशय का वस्तावेजो साक्ष्य होगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक उपनियम (1) के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर, संबंधित व्यक्ति को सेवान्युक्त या सेवा से निवृत्त कर सकेगा।

25. भर्ती के समय मिथ्या/गलत जानकारी देने के आधार पर सेवान्युक्त/सेवा से निवृत्त की प्रक्रिया—

यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, उपनियम के अधीन दत्ते हुए, किसी व्यक्ति को, सेवा में उस व्यक्ति द्वारा भर्ती के समय मिथ्या/गलत जानकारी देने के आधार पर सेवान्युक्त या सेवा से निवृत्त कर सकेगा। उक्त व्यक्ति की सेवान्युक्त/सेवा से निवृत्त के पहले उसे कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी।

26. अस्वस्थता के कारण अयोग्यता के आधार पर सेवा निवृत्ति/सेवा से निवृत्त/सेवान्युक्त—

(1) जब उपनियम के अधीन कोई व्यक्ति अस्वस्थ बल चिकित्सा सेवा विनियमों के अधीन ठहरे किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा तटरक्षक सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसे इस नियम में अधिकाधिक प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, या सेवान्युक्त किया जा सकेगा।

(2) चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि व्यक्ति तटरक्षक सेवा के किसी भी रूप के लिए स्थायी रूप से अयोग्य है, तत्काल एक सूचना जारी करेगा जिसमें उस रोग या निशक्तता की प्रकृति जिससे वह पीड़ित है और चिकित्सा बोर्ड का निष्कर्ष विनिर्दिष्ट होगा तथा उसे यह भी सूचित करेगा कि निष्कर्ष को देखते हुए उसे सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त या सेवान्युक्त किया जा सकता है।

परन्तु जहाँ चिकित्सा बोर्ड का रोग में व्यक्ति किसी मानसिक रोग से पीड़ित है और उस व्यक्ति को उस रोग या निशक्तता की प्रकृति के बारे में संशुद्धि करना अशक्य है या व्यक्ति अपना हित समझने में अयोग्य है, वहाँ रोग या निशक्तता की प्रकृति व्यक्ति के उम्र निकट नब्बे की जिसे उपनियम (3) के अधीन भर्ती देने का निर्धारण होगा, संशुद्धि की जाएगी।



(3) ऐसी सूचना में यह भी विनिर्दिष्ट होना कि व्यक्ति सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, जिक्रित बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध जिक्रित बोर्ड के प्रत्यक्ष को अपील दे सकेगा।

(4) यदि कोई अपील उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती है तो व्यक्ति को, अधिकारियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा और अभ्यावेष्टि (व्यक्तियों की दशा में तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक द्वारा, उस आयाग के आदेश द्वारा, सेवा निवृत्त/सेवा से निर्मुक्त या सेवान्मुक्त किया जा सकेगा।

(5) यदि कोई अपील उपनियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर दी जाती है तो अध्यक्ष, जिक्रित बोर्ड, उसे सशस्त्र बल जिक्रित सेवा विनियमों के अधीन गठित जिक्रित बोर्ड (अपील) के पास उस अपील पर उसके विनिर्णय के लिए निविष्ट करेगा। मामले से संबंधित प्रतिलिखों के साथ जिक्रित बोर्ड के निष्कर्षों, तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को भेजे जाएंगे। यदि दोनों जिक्रित बोर्डों के निष्कर्षों में कोई मतभेद न हो तो व्यक्ति को, अधिकारियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा और अभ्यावेष्टित व्यक्तियों की दशा में तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक द्वारा, उस आयाग के आदेश द्वारा, सेवा निवृत्त/सेवा से निर्मुक्त या सेवान्मुक्त किया जा सकेगा।

(6) किसी जिक्रित बोर्ड और जिक्रित बोर्ड (अपील) के निष्कर्षों में मतभेद होने की दशा में, अधिकारियों के मामले में महानिरीक्षक या अभ्यावेष्टित व्यक्तियों के मामले में तटरक्षक मुख्यालय में महानिरीक्षक मामले को, सशस्त्र बल जिक्रित सेवा विनियमों के अधीन उस प्रयोजन के लिए गठित जिक्रित बोर्ड (पुनर्विलोकन) के पास अल्पसंख्यता के कारण अयोग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को सेवा निवृत्त/सेवा से निर्मुक्त या सेवान्मुक्त करने से पूर्व राय के लिए भेजेगा।

27. अपने अनुरोध पर सेवान्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया —

(1) तटरक्षक का कोई सदस्य, आपदाधिक मामलों में, अर्थात् अनुकम्पा के आधारों पर, अर्थात् ऐसे मामलों में जहाँ यह स्पष्ट हो कि निःसंदेह तात्त्विक कठिनाई तटरक्षक के सदस्य या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को सेवा में उसके रखे रहने से होगी, अपनी सेवान्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवा निवृत्ति अभिलषित कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखने हुए, सेवानिवृत्ति की प्राप्ति अभिलषित करने से पहले अधिकारी की सेवान्मुक्ति सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति अनुज्ञात कर सकेगा। सेवान्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति का प्रयत्न केन्द्रीय सरकार के विवेक के भीतर का मामला होगा।

(3) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, किसी अधिकारी से भिन्न तटरक्षक के किसी सदस्य को अनुकम्पा के आधारों पर सेवान्मुक्त, सेवा से निर्मुक्त या सेवानिवृत्ति कर सकेगा।

(4) अनुकम्पा के आधार पर सेवान्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवा निवृत्ति के आवेदन को कमान अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कमान के माध्यम से तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को अभिलषित किया जाएगा।

28. वह तारीख जिससे सेवा निवृत्ति/पदच्युति/सेवा से हटाया जाना/पदत्याग/सेवान्मुक्ति प्रभावी होगी :

(1) अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाए जाने, पदत्याग या सेवान्मुक्त की तारीख, यथास्थिति सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाए जाने, पदत्याग या सेवान्मुक्ति वाले आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी।

(2) अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाए जाना, पदत्याग या सेवान्मुक्ति श्रुतलब्धी नहीं होगी।

#### अध्याय 5

#### विहित अधिकारी और प्राधिकारी

29. विहित अधिकारी और प्राधिकारी - नीचे को सारणों के स्तंभ (3) और (4) में वर्णित अधिकारी और प्राधिकारी, उक्त सारणों के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्तंभ (1) में उल्लिखित धाराओं के अधीन विहित प्राधिकारी होंगे।

अधिनियम की धारा	प्रयोजन	विहित अधिकारी	विहित प्राधिकारी
1	2	3	4
धारा 8	अपथ विधान या प्रतिज्ञान कराने के लिए	कोई अधिकारी	---
धारा 9	पदत्याग और पद से निकाले जाने के लिए	---	1. अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार अभ्यावेष्टित व्यक्तियों के लिए तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक
धारा 13(1)	उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन संगण, आदि बनाने के लिए लिए पूर्व संजूरी प्रदान करने के लिए	---	1. अधिकारियों के लिए महानिरीक्षक 2. अभ्यावेष्टित व्यक्तियों के लिए तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक
धारा 63(1) धारा 71	तटरक्षक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम के अधीन कार्यवाहीया प्रारंभ करने के लिए दंड न्यायालय या तटरक्षक न्यायालय के चुनाव का विनिर्णय करने के लिए	कमान्डर क्षेत्रीय मुख्यालय वह कमान अधिकारी जिसके समन्वय के अधीन नियुक्त सेवा कर रहा है	---
धारा 86(1)	पदों, विवरणियों या अन्य वस्तुओं पर हस्तक्षेप करने के लिए	निदेशक (कार्मिक) तटरक्षक मुख्यालय और सारणाधिक अधिकारी, नाविकों का व्यूरो	---
धारा 89	1. विद्वत् विचार के किसी व्यक्ति के विचारण के संबंध में कार्यवाही करने के लिए	वह अधिकारी जिसने तटरक्षक मुख्यालय द्वारा मूल विचारण के लिए आदेश दिया	---

1	2	3	4
	2. विचारण में हाजिर होने के लिए स्वा- स्थता का प्रमाण-पत्र	---	पायलखाना या सुरक्षित अभिरक्षा के उच्च स्थान का, जहाँ व्यक्ति रखा गया है, विकित्सा अधिकारी
धारा 97	मृत्यु से दण्डविषट्ट किए गए किसी व्यक्ति की अंतरिम अभिरक्षा का आदेश देने के लिए	यह कमान अधिकारी जिसके समावेश के अधीन अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा था।	---
धारा 98	मृत्यु के दण्डादेश के निष्पादन के लिए निवेष्ट देने के लिए	यह कमान अधिकारी जिसके समावेश के अधीन, अभियुक्त सेवा कर रहा था	---
धारा 100(1)	किसी सिविल कारागार में परिरोध के लिए निदेश देने के लिए	यह अधिकारी जिसने तटरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण के लिए आदेश दिया।	---
धारा 100(2)	किसी व्यक्ति के किसी सिविल कारागार में परिरोध के लिए वारंट जारी करने के लिए	दण्डादेश के अधीन व्यक्ति का कार्यपालक अधिकारी।	---
धारा 103	किसी सिविल कारागार के आस्थाधिक अधि- कारी को कोई दण्डादेश प्रपास्त करने या अधिकारी उसमें फेरफार करने वाले आदेश से युक्त वारंट जारी करने के लिए	दण्डादेश के अधीन व्यक्ति का कमान कारी	---

30. धारा 67 के प्रयोजन के लिए, स्तंभ (1) में वर्णित और स्तंभ (2) में वर्णित रैंक धारण करने वाले प्राधिकारियों को, नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित सीमा तक दंड देने की शक्ति होगी:

## सारणी

प्राधिकारी	रैंक	यह सीमा जिस तक दंड दिया जा सकता है
1	2	3
1. कमान अधिकारी	सभी रैंक	सभी दंड
2. कार्यपालक अधिकारी	(1) कमांडेंट	(1) अभ्यावेशित सभी व्यक्तियों के 48 घंटे तक छुट्टी संग करने के प्रथम अपराध के लिए वेतन और भत्तों का अपकर्तन। (2) नाविकों को 14 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रतिरिक्त कार्य और कवायद (ड्रिल) (3) अभ्यावेशित सभी व्यक्तियों को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए छुट्टी का रोकना जाना। (4) अभ्यावेशित सभी व्यक्तियों की हस्तर्षा।
	(2) उपकमांडेंट,	(1) अभ्यावेशित सभी व्यक्तियों के 36 घंटे तक छुट्टी संग करने के प्रथम अपराध के लिए वेतन और भत्तों का अपकर्तन। (2) नाविकों को 7 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रतिरिक्त कार्य और कवायद। (3) अभ्यावेशित सभी व्यक्तियों को 15 दिन से अधिक अवधि के लिए छुट्टी का रोकना जाना। (4) अभ्यावेशित सभी व्यक्तियों की हस्तर्षा।
	(3) सहायक कमांडेंट	(1) नाविकों को 7 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रतिरिक्त कार्य और कवायद। (2) अधीनस्थ अधिकारियों से निरस्त व्यक्तियों को 15 दिन से अधिक अवधि के लिए छुट्टी का रोकना जाना। (3) अधीनस्थ अधिकारियों से निरस्त व्यक्तियों की हस्तर्षा।
3. निगरानी अधिकारी/वैजिक अधिकारी	सहायक कमांडेंट और ऊपर	(1) नाविकों को एक दिन के लिए प्रतिरिक्त कार्य और कवायद। (2) नाविकों की हस्तर्षा।

31. शपथ या प्रतिज्ञान-सदृशक या प्रत्येक राज्य, निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा :—

राज्य/प्रतिज्ञान का प्राकृ

मैं, क. ग. ईश्वर की शपथ लेता हूँ/मन्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और जैसा कि मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध हूँ, ईमानदारी से और बकाशारी से तटरक्षक की सेवा करूँगा और वायू भूमि या समुद्र मार्ग से जहाँ कहीं भी से जाने का आदेश मिलेगा, वहाँ जाऊँगा और मैं भारत के संघ के राष्ट्रपति के सब समादेशों का और अपने उपरिस्थापित किसी अधिकारी के समादेशों का अपने जीवन अंतिम उठा कर भी पालन करूँगा।

हस्ताक्षर—

प्रतिहस्ताक्षर—

(शपथ दिलाने वाले व्यक्ति का नाम

और पदनाम)

अध्याय—6

शिकायत और अध्यावेदन

32. उच्चतर प्राधिकारियों को शिकायत.—(1) यदि कोई अधिकारी या अध्यावेष्टित व्यक्ति यह समझता है कि उसे कोई वैयक्तिक, अत्याचार, अन्याय या अन्य बुरा बर्ताव सहन करना पड़ा है या उसके साथ किसी भी प्रकार से अनुचित रूप से बर्ताव किया गया है या वह अपने कल्याण को प्रभावित करने वाला अध्यावेदन करना चाहता है या सेवा से संबंधित कोई सुझाव देता है तो वह उसे अपने बरिष्ठ अधिकारी के ध्यान में लाएगा।

(2) यह उस बरिष्ठ अधिकारी, जिसे अध्यावेदन दिया गया है, का कर्तव्य होगा कि वह उसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के पास छोड़ने के लिए प्रेरित करे।

(3) इन नियमों में उल्लिखित रीतियों के सिवाय, बरिष्ठ अधिकारी/प्राधिकारी में अनुरोध मांगने की कोई अन्य रीति निषिद्ध है।

33. शिकायत किसको की जाएगी.—(1) यदि, शिकायतकर्ता, तटरक्षक पोत का कोई कमान अधिकारी है, तो उसकी शिकायत लिखित रूप में होगी और उसके अध्यावेष्टित बरिष्ठ अधिकारी को संबोधित होगी।

(2) यदि शिकायतकर्ता, तटरक्षक पोतों में से किसी एक पोत में, सेवा करने वाला कोई अधिकारी है तो उसकी शिकायत मौखिक रूप से कमान अधिकारी को की जाएगी जिसके द्वारा कोई शिकायतकर्ता उस प्रयोजन के लिए कमान अधिकारी से अथलोकन करने के लिए मौखिक अनुरोध करेगा। यदि शिकायतकर्ता कोई अधिकारी है तो ऐसा अनुरोध कार्यपालक अधिकारी को माफ़ी किया जाएगा और यदि शिकायतकर्ता विभाग का प्रधान है तो अनुरोध स.घे. कमान अधिकारी से किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने वाला कोई अधिकारी है, तो अनुरोध, प्रथमतः विभाग के प्रधान में किया जाएगा।

(3) यदि शिकायतकर्ता अध्यावेष्टित व्यक्ति है, तो उसकी शिकायत मौखिक रूप से कमान अधिकारी को की जाएगी। कमान अधिकारी से अथलोकन करने का अनुरोध शिकायतकर्ता के प्रभागीय या विभागीय अधिकारी का माफ़ी कार्यपालक अधिकारी में किया जाएगा। उसके पास या उसके स्थापन से नियोजित अध्यावेष्टित व्यक्ति अपनी शिकायत उस अधिकारी से करेगा जिसके समावेश में वह उस समय हो।

34. शिकायतकर्ता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम—(1) कोई शिकायत, ऐसे तथ्यों के, जो शिकायत से संबंधित हैं, कथन तक और स्वयं शिकायतकर्ता के अधिकृत परिणामों तक सीमित होगी।

(2) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त शिकायत अनुज्ञात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत स्वयं करेगा।

(3) मौखिक रूप से या लिखित रूप से, शिकायत करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि—

(क) शिकायत में तथ्यों का कथन उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है, और

(ख) शिकायत ऐसी भाषा में नहीं की गई है जो प्रशिक्षित, पक्षपातपूर्ण या अनुशासन के लिए आवश्यक है।

35. शिकायत को किस प्रकार निपटाया जाएगा :—(1) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, कमान अधिकारी, या उसे प्राप्त करने वाला अन्य अधिकारी, स्वयं का यह समाधान करेगा कि शिकायत इन नियमों के अनुसार की गई है। उसके पश्चात् वह अपने विवेक का, जो उसे ठीक प्रतीत हो, प्रयोग करते हुए उसका निपटारा करेगा और शिकायतकर्ता को अपने विनिश्चय के बारे में सूचित करवाएगा।

2 यदि शिकायत प्राप्त करने वाला कमान अधिकारी या अन्य अधिकारी इस प्रकार की गई शिकायत का उपचार करने में इंकार कर देता है या उसका उपचार करने में असमर्थ है, तो शिकायतकर्ता श्राव्य सहित यह निवेदन कर सकेगा कि उसे अपनी शिकायत लिखित रूप में करने के लिए अनुज्ञात किया जाए। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, कमान अधिकारी, या अन्य अधिकारी, शिकायतकर्ता को इस विषय पर पुनः विचार करने के लिए 24 घंटे का समय देगा। उसके पश्चात् शिकायतकर्ता, अपनी शिकायत कमान अधिकारी या अन्य अधिकारी को लिखित रूप में देगा, जो बाद में शिकायत को उस पर अपनी टिप्पणी सहित अगले बरिष्ठ अधिकारी को अर्पित करेगा।

(3) यदि शिकायतकर्ता, अपनी शिकायत के संबंध में विनिश्चय में तनुष्ट नहीं है या यदि वह, यथास्थिति, अपनी शिकायत के प्रस्तुत करने की तारीख या उसे अगले बरिष्ठ प्राधिकारी को भेजने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर मांगी गई प्रतिलोभ प्राप्त नहीं करता है, तो वह यह अनुरोध कर सकेगा कि उसकी शिकायत को अगले बरिष्ठ अधिकारी को और उसके बाद, यथास्थिति, महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार को अर्पित किया जाए और ऐसे सब अनुरोध का अनुपालन किया जाएगा। शिकायतकर्ता के लिए यह न्यायोचित होगा कि वह उस दशा में सीधे अगले बरिष्ठ प्राधिकारी के पास अपनी शिकायत करे, यदि वह अपनी शिकायत के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं करता है।

अध्याय 7

जांच बोर्ड

36. जांच बोर्ड का संयोजन

जब कभी कोई ऐसा मामला उत्पन्न हो जिस पर महानिदेशक या क्षेत्रीय मुख्यालयों के कमांडरों को पूर्ण रूप से जानकारी अपेक्षित हो, उक्त प्राधिकारी द्वारा एक जांच बोर्ड संयोजित किया जा सकेगा।

37. जांच बोर्ड का गठन

बोर्ड में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक अधिकारी और कम से कम दो ऐसे सदस्य होंगे जो या तो अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी होंगे या दोनों होंगे ऐसे व्यक्ति भी, जो अधिनियम के अधीन नहीं हैं, स्वयं के रूप में उस समय नियुक्त किए जा सकेंगे जब बोर्ड को किसी विशिष्ट प्रगति के मामलों का अन्वेषण करना है और अधिनियम के अधीन अर्हताएं वाले अधिकारी उपलब्ध न हों।

38. बोर्ड के कर्तव्य

(1) बोर्ड ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो बोर्ड संयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(2) ऐसे निदेश सबैव लिखित रूप में होंगे और अत्यावश्यकता के मामलों में संकेत द्वारा पहुंचाए जा सकेंगे। किन्तु, बोर्ड संयोजित करने वाला आदेश उस फोरमेट में होगा जो उपायध में दिया गया है।



## 39. जांच बोर्ड के लिए प्रक्रिया

(1) बोर्ड इन नियमों के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त तटरक्षक आदेशों और संयोजक प्राधिकारी के विहित अनुदेशों द्वारा भी मार्गदर्शित होगा, परन्तु यह तब जब कि तटरक्षक आदेश और विहित अनुदेश इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) जांच बोर्ड का कार्यवाहियों करना के लिए खुली हुई नहीं होगी। केवल ऐसे व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकेंगे जिन्हें बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

(3) बोर्ड द्वारा प्रेषण किए गया प्रत्येक साक्षी का निम्नलिखित शब्दों में, जो कार्यवाहियों में लेखबद्ध किए जाएंगे, सूचित किया जाएगा: "आप किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर सकते हैं, जिसके उत्तर की प्रवृत्ति आपको किसी आस्ति या सम्पत्ति की रक्षा में डाल सकती है। इसके संबंध में आपलिप्त करना आप पर निर्भर करेगा और इसका विनिवृत्त करना बोर्ड पर निर्भर करेगा कि आपको प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं।"

(4) जब कभी किसी जांच में तटरक्षक में रोका कर रहे व्यक्ति का चरित्र या क्याप्रियावित होती हो या उसका परिणाम किसी हानि या नुकसान के लिए दायित्व या उत्तरदायित्व के स्रोत के रूप में हो या वह किसी निम्न या ग्राह्यता या स्थानीय आदेशों के अन्तर्गत के लिए की जाती है, ऐसे व्यक्ति को जांच के दौरान शुरू से अन्त तक उपस्थित रहने के लिए और कोई वापस करने तथा कोई ऐसा साक्ष्य देने, जो वह देने की इच्छा करे, और किसी ऐसे साक्षी की प्रतिवृत्ति करने, जिसका साक्ष्य उसकी राय में उसे प्रभावित करता है तथा अपनी प्रतिवृत्ति में कोई साक्षी पेश करने के लिए पूरा उत्तर दिया जाएगा। बोर्ड का गैरआसीत अधिकारी ऐसी कारवाही करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार प्रभावित और पूर्ण अधिसूचित न किया गया कोई ऐसा व्यक्ति इन नियमों के अधीन अपने अधिकारियों की अपेक्षा की स्वीकार करेगा कि उसे पूर्णतः संतुष्ट है।

(5) बोर्ड का कार्यवाहियों, तत्समय प्रवृत्त तटरक्षक आदेशों में वर्णित जिन्हें नियमों और संयोजक प्राधिकारों द्वारा दिए गए किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अभिलेखित का जाएगा। ऐसे कार्यवाहियों के कार्यवाह में दिए गए सब साक्ष्य का संक्षेप नोट किया जाएगा तथा सभी प्रश्नों और उत्तरों की कार्यवाह में आयोगीत एक कम से संक्षेपित किया जाएगा।

(6) बोर्ड का कार्यवाहियों या बोर्ड के समक्ष किया गया कोई संस्कृत नक्शा या चित्र या किसी प्रश्न का उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति, उसी घंटे के किसे सम्मुख सब संयोजित विधियों के अधीन है, के विरुद्ध माध्य में माध्य नहीं होगा, न ही कोई कार्यवाहियों को बाध को रोक जिससे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया जाएगा। परन्तु इन नियमों का कोई भी बात कि साक्षी की प्रतिवृत्ति के प्रयोजन के लिए कार्यवाहियों का उपयोग किए जाने के लिए नहीं है।

## 40. जांच बोर्ड का एग्रीजित होगा

(1) कोई जांच बोर्ड,—

(क) तटरक्षक पंक्तियों, अलवानों या वायुयान का खोला, उत्कूलन या परिसंरक्षित होता,

(ख) किसी पंक्ति के फलक/स्थान/वायुयान पर किंसा अधिका की अवस्थिति, गुरुत्व या उसे सम्बंधित शक्ति,

(ग) ऐसी वर्गीकृत पुस्तकें या प्रमाणों, जिनमें सुरक्षा संग जलबलित हो, का खो जाना,

(घ) सरकारी सम्पत्ति या गंडार का नुकसान या हानि या लोक धन का हानि,

159 GI/86—2

(ड) प्रादेशिक प्रमाणों या सम्पत्ति की हुई नुकसान, जिससे बाधा केन्द्र नगरपाल या तटरक्षक के विरुद्ध कोई दावा किए जाने का सम्भव हो,

जैसे महान के किताब मामलों में अपेक्षा करने के लिए संयोजित किया जा सकता।

41. जांच बोर्ड का कार्यवाहियों पर कार्यवाही ज्ञान बोर्ड का कार्यवाहियों, बोर्ड के पठन अधिकाधिक द्वारा संयोजित प्राधिकारों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कार्यवाहियों के प्राप्त होने पर, संयोजक प्राधिकारी—

(1) ऐसी कार्यवाही करेगा जो उसी अधिकारिता के तहत है और जो यह करता हो सकता है।

(2) उन्हें, उन पर अपनी रिपोर्ट सहित, उत्तुष्ट प्राधिकारों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसे प्राधिकारों के आदेशों के अधीन ऐसा करना आवश्यक हो।

42. बोर्ड की कार्यवाहियों की प्रतिनिधि निम्नलिखित व्यक्ति बोर्ड की कार्यवाहियों की एक प्रति प्रति प्राप्त करने के इच्छा करेंगे:—

(क) अधिनियम के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति जिसका किसी ऐसे मामले या बात, जिसकी रिपोर्ट बोर्ड द्वारा की गई है, की जांच विचारण किसे तटरक्षक न्यायालय द्वारा किया गया है, या

(ख) जब तक कि महाविदेश किन्हीं कारणों से अथवा आदेश न दे सरकारी सेवा में का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र, आचरण या क्षमता महाविदेश की राय में, बोर्ड के तत्समय में रोका जान से प्रभावित होती है।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रभाव के लिए कार्यवाहियों के अंतर्गत बोर्ड के निष्कर्ष भी होंगे किन्तु इनके अंतर्गत बोर्ड की सकारित नहीं होगी।

## अध्याय 8

## आवेदन और अर्जियां

43. किसी तटरक्षक न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश के विरुद्ध आवेदन और अर्जियां

(1) अधिनियम के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विचारण किसी तटरक्षक न्यायालय द्वारा किया गया, मुख्य विधि अधिकारी को अधिनियम की धारा 117 के अधीन तटरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) कोई अर्जी, अधिनियम की धारा 119 में वर्णित किसी प्राधिकारी को दी जाने के लिए अनुज्ञात होगी।

44. परिसीमा की अवधि न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन उस तारीख से जिसको तटरक्षक न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित किया गया था, 31 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 119 के अधीन कोई अर्जी तटरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाहियों के संबंध में मुख्य विधि अधिकारी द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन पर महाविदेश के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

परन्तु ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियों या मुख्य विधि अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन पर महाविदेश के आदेशों की प्रतिनिधि अभिप्राय करने में लिए गए समय को यथास्थिति 21 दिन या 3 मास की अवधि को संगणना करने में नहीं लिया जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त कोई आवेदन, यथास्थिति, महाविदेश या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस दण्डा में ग्रहण किया जा सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जो आवेदक के नियंत्रण के बाहर थे।

## 45. आवेदन और अर्जी प्रस्तुत करने का ढंग

(1) कोई आवेदन या कोई अर्जी स्वयं प्रस्तुत की जा सकती या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती। या दो प्रतियों में होगी

और आवेदन द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इसमें उन प्राधारों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा जिन पर दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरुद्ध आदेश किया गया है। यदि आवेदन अधिनियम की धारा 117 के अधीन है, तो आवेदक को यह भी कथित करना चाहिए कि क्या वह स्वयं या किसी विधि व्यवसायी या तटरक्षक के किसी अधिकारी की मार्फत मुने जाने की इच्छा करता है। यदि अर्जी अधिनियम की धारा 119 के अधीन है, तो वैयक्तिक सुनवाई करना अपेक्षित नहीं है।

(2) धारा 117 के अधीन आवेदन सीधे मुख्य विधि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 119 के अधीन अर्जी, उस कमांडर तटरक्षक क्षेत्र, जिसके समावेश में विचारण हुआ था, की मार्फत प्रस्तुत की जाएगी। कमांडर तटरक्षक क्षेत्र, उसे अर्जी टिप्पणियों सहित एक मास के अवधि के भीतर महानिदेशक को प्रेषित करेगा।

प्रेषक :

स्थान :

तारीख :

प्रेषिता :

जांच बोर्ड के लिए आदेश

आपसे, जांच बोर्ड के रूप में, जिनका पठावली अधिकारी \_\_\_\_\_ होगा, \_\_\_\_\_ में \_\_\_\_\_ 198 को \_\_\_\_\_ बजे सम्मेलन होने और \_\_\_\_\_ की परिस्थितियों का पूर्णतया और सावधानी से अन्वेषण करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

2. आपके रिपोर्ट के साथ मौखिक रूप से लिए गए साक्ष्य के कार्यवृत्त होंगे और उसमें साक्ष्य द्वारा प्रकट किए गए मामले के गुणवत्ता पर आपकी राय की प्रतिबिम्बित होगी; उसमें यह भी पूर्णतः कथित होगा कि किसका, क्या किस व्यक्ति का, और किस सोमा तक, दोष माना जा सकता है।

3. कार्यवृत्त में प्रश्न की आधीप्रांत एक क्रम में संयोजित किया जाएगा, और कार्यवृत्त तथा रिपोर्ट पर बोर्ड के पठावली अधिकारी और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। परीक्षाधीन साक्षी का नाम, जो आने वाले रिपोर्ट और कार्यवृत्त के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर मॉड किया जाएगा।

4. कार्यवृत्त और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि बोर्ड की कार्यवाहियों में निविष्ट सब कागजपत्र के साथ मूल (या यदि मूल उपलब्ध नहीं है तो उनकी प्रतिलिपियाँ) और कार्यवृत्त की सभी प्रतिलिपियाँ हैं, तथा कार्यवृत्त की प्रतियों और उन्हें प्रस्तुत करने से संबंधित नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है।

5. कोई ऐसा अन्य नामला, जो कार्यवाहियों से उत्पन्न होता है और जिस पर बोर्ड विचार करता है, संयोजक अधिकारी की जानकारी में लाया जाएगा और वह पूरा रिपोर्ट का विषय होगा।

6. आप तटरक्षक (साधारण) नियम, 1986 के अध्याय 7 के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

7. \_\_\_\_\_ ऐसे साक्षियों, जिनकी बोर्ड द्वारा परीक्षा करने की अपेक्षा की जाए, के हाजिर किए जाने की व्यवस्था करेगा।

8. \_\_\_\_\_, किसी गोपनीय जांच के दीर्घाव आकृतिक की ओर आवश्यक लेखन-सामग्री की व्यवस्था करेगा।

9. सभी सुसंगत कागजपत्र, बोर्ड के पठावली अधिकारी को इसके साथ सौंपे जाते हैं जो उन्हें समस्त अंकुश में कार्यवृत्त के साथ लौटा देगा।

(संयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर)

## MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 1986

S.R.O. 4(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (d), (e), (f), (k) and (l) of sub-section (2) of section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

## CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Coast Guard (General) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions. In these Rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) ;
- (b) "Annexure" means Annexure appended to these Rules ;
- (c) "Board" means the Board of Inquiry convened under Rule 36 ;
- (d) "Coast Guard Order" means the order issued by the Director General of the Coast Guard ;
- (e) "Coast Guard Region" means a Coast Guard Region specified in sub-rule (3) of Rule 4 ;
- (f) "Executive Officer" means an officer who carries out executive duties of the ship ;
- (g) "Regional Commander" means the Commander, Coast Guard Region specified in sub-rule (2) of Rule 4 ;
- (h) Words and expressions used but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Reports and Application.—Any report or application directed by these rules to be made to a Coast Guard authority, shall be made in writing through the proper channel, unless the said authority on account of exigencies of service or otherwise dispenses with the writing.

## CHAPTER II

### ORGANISATION

4. Constitution of the Coast Guard.—(1) The Coast Guard shall consist of officers, subordinate officers, sailors and other enrolled persons, appointed to, or enrolled into, the Coast Guard Service.

(2) The Director General shall exercise command through the following authorities :—

- (a) The Commander, Coast Guard Region, West ;
- (b) The Commander, Coast Guard Region, East ;
- (c) The Commander, Coast Guard Region, Andaman and Nicobar Islands ; and
- (d) The Commander, Coast Guard Customs.

(3) (a) The Coast Guard Region, West, shall comprise of the Coastal areas and the maritime zones of India along the coastal areas of the States of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Lakshadweep ;

(b) The Coast Guard Region, East, shall comprise of the coastal areas and the maritime zones of India along the coastal areas of the States of Tamil

Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal and the Union Territory of Pondicherry ;

(c) The Coast Guard Region, Andaman and Nicobar Islands, shall comprise of coastal areas and the maritime zones along the coastal areas of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

(d) The Commander, Coast Guard Customs, shall exercise operational and administrative control on all ships assigned to him by the Director General.

5.—Each Coast Guard Region shall be further divided into districts and each district shall be under the supervision of the District Commander to be appointed by the Director General.

6.—The Director General shall establish such number of stations and shall assign such number of ships to each Coast Guard Region|district|station as he may think fit depending upon the exigencies of the service from time to time.

## CHAPTER III

### RANK AND COMMAND

7. Classifications and Ranks.—The officers and other members of the Coast Guard shall be classified in accordance with their ranks in the following categories, namely :—

(a) Officers.—

- (i) Director General ;
- (ii) Inspector General ;
- (iii) Deputy Inspector General ;
- (iv) Commandant ;
- (v) Deputy Commandant ;
- (vi) Assistant Commandant.

(b) Subordinate Officers.—

- (i) Pradhan Adhikari|Pradhan Sahayak Engineer ;
- (ii) Uttam Adhikari|Uttam Sahayak Engineer ;
- (iii) Adhikari|Sahayak Engineer.

(c) Sailors.—

- (i) Pradhan Navik|Pradhan Yantrik ;
- (ii) Uttam Navik|Uttam Yantrik ;
- (iii) Navik|Yantrik.

8. Branches.—(1) The branches into which officers are classified shall be, —

- (a) General Duties ;
- (b) Technical.

(2) The branches into which enrolled persons are classified shall be, —

- (a) General Duties ;
- (b) Technical ;
- (c) Domestic ;
- (d) Enrolled followers.

9. Specialisations.—The officers and enrolled persons shall be eligible for specialisation as follows, namely :—

Categories of personnel	Specialisation	Sub-Specialisation
1	2	3
(a)(i) Officers (General Duties)	Pilot Navigator. Law. Pollution Control. Salvage. Diving.	Not applicable
(ii) Officers (Technical)	Aviation Engineering. Electrical Engineering. Electronic Engineering. Pollution Control. Salvage. Naval Architecture. Marine Engineering.	Not applicable
(b)(i) Subordinate officers and sailors (General Duties)	Seaman.  Mechanics.	Gunners Mats. Quarter Master. Radio Operator. Airman. Diver. Engineering. Air Engineering. Electrical. Air Electrical. Air Radio.
(ii) Subordinate officers and sailors (Technical)	Marine Engineering. Air Engineering. Electrical Engineering. Air Electrical Engineering. Electronic Engineering. Air Electronic Engineering. Hull Engineering.	Not applicable.
(iii) Subordinate officers and sailors (Domestic)	Supply Assistants. Cooks. Stewards.	Not applicable.

10. Command of Coast Guard Ships.—(1) Command of Coast Guard Ships, vessels, aircrafts or such establishments as may be promulgated by the Director General will be considered as operational command.

(2) Generally officers and enrolled persons of the General Duties Branch shall exercise operational command, or direct any work or undertaking which requires the co-operation of different branches of the Coast Guard Service. It may be conferred on other officers and enrolled persons by appointment or by direction by the Director General.

(3) Command of ships|vessels|aircrafts shall be limited to qualified officers of the General Duties branch and enrolled persons of seaman specialisation, except when conferred by superior authority on other persons qualified by ability and experience.

(4) Command of Coast Guard ships|vessels, establishments and aircrafts may also be exercised by the officers and sailors of the Indian Navy while on deputation to the Coast Guard, when specifically appointed by the Director General.

(5) Technical Officers appointed in command of shore establishments may exercise such functions of command as may be necessary for the proper performance of their duties.

(6) Officers holding appointments under civil departments of the Government shall not, without the

express orders of the Director General, assume any command over, or issue any orders to, the personnel of the Coast Guard, other than to those officers and enrolled persons who are serving under them in their respective departments.

11. Officer in Command—Rank and precedence—Officers in command of Coast Guard ships shall take rank and precedence over the officers placed under their command on all occasions, whether on shore or afloat.

12. Command in Temporary Absence of Commanding Officer.—Except in a shore establishment, the senior general duties officer on board (other than an officer appointed additional for staff or special duties, or an officer not qualified to command ships|vessels) shall, in the temporary absence of the Commanding Officer, assume the powers and duties of the Commanding Officer. In a shore establishment, command shall devolve in the branch of the Commanding Officer. If no officer of the Commanding Officer's branch is present, then command shall devolve on the seniormost officer present ; but command shall not devolve on any officer appointed additional for staff or special duties or for courses.

13. Authority of officer of the Watch.—Every officer below the rank of the Deputy Inspector General (not being either the Executive Officer or the Commanding Officer of the ship for the time being) and



enrolled person shall be subordinate to the officer of the watch, whatever may be his rank, in regard to the performance of the duties with which he is charged.

14. How Officers and Enrolled persons are to be borne.—(1) Officers and enrolled persons serving afloat or ashore shall be borne on the books of the ship or establishment or station in which they are serving or to which they are attached.

(2) When it is desired that an officer borne additional for staff or special duties should practice or gain experience in ship handling and the like, authority for him to take charge of a watch at sea or in harbour may be given by the Commanding Officer :

Provided that nothing in this rule shall put him in the line of succession to command.

15. Officer promoted.—An officer, who is promoted shall continue to perform the duties he has been assigned, and shall take rank and command of the new rank only if he is reappointed to his ship in the higher rank.

16. Officers on Deputation.—Officers deputed by the competent authority to do duty on board any other ship, although borne as supernumeraries, shall take the same rank and command, and be considered in every respect for the time they are so employed, as if they actually belonged to the complement.

17. Officers taking passage.—Any officer taking passage in one of the Coast Guard ships, may, though borne as supernumerary, be ordered to do duty if inferior or junior in rank to the Executive Officer of the ship in which he is embarked. While so employed he shall take the same rank and command, and shall be considered in every respect as if he actually belonged to the complement. In the event of the death of the Commanding Officer of the ship, the acting command thereof shall vest in the officers mentioned in rule 12 and in no case shall be assumed by a supernumerary officer except on the express authority from the Director General.

18. Authority of Army, Navy and Air Force Officers.—An officer of the Army, Navy and Air Force

appointed to the Coast Guard shall have and exercise all such powers as are vested in or may be exercised by an officer of the Coast Guard of the corresponding rank or holding a corresponding appointment.

19. Subject to the provisions of sections 57 and 58 of the Act, when a person subject to the Act is attached to any body, or serving in a unit, or admitted as a patient in a hospital of the regular Army, Navy or Air Force, the Commanding Officer of such body, unit or hospital shall exercise all powers of Command over officers junior to him in rank and all powers of command and punishment over enrolled personnel.

#### CHAPTER IV

#### RETIREMENT, DISMISSAL, REMOVAL, DISCHARGE OR RELEASE

20. Retirement.—(1) Retirement age for officers holding a rank higher than that of a Commandant shall be fifty-eight years and for officers of other ranks it shall be fifty-five years.

Provided that the Central Government may extend the retirement age of :—

- (a) An officer of the rank higher than that of a Commandant for a period of one year at a time but not, in any case, beyond the age of sixty years ;
- (b) Officers of other ranks for a period of one year at a time but not, in any case, beyond the age of fifty eight years.

(2) Retirement age of subordinate officers and sailors shall be fifty five years.

21. Dismissal, removal, discharge or release.—(1) Authorities specified in column 1 shall be competent to authorise dismissal, removal, discharge or release of the members of the Coast Guard specified in column 2, on the grounds stated in the corresponding entries in column 3, in accordance with the procedure specified in column 4 of the Table annexed hereto. Any power conferred by this rule on any of the aforesaid authorities may also be exercised by any other authority superior to it.

TABLE

Competent Authority	Member of the Coast Guard	Grounds on which service can be terminated	Procedure for termination of service
1	2	3	4
Central Government	Officers	(i) Misconduct	As per procedure prescribed under Rule 22.
		(ii) Unsuitability	As per procedure prescribed under Rule 22.
		(iii) Unsatisfactory progress in training	As per procedure prescribed under Rule 24.
		(iv) Furnishing False/wrong information at the time of recruitment.	As per procedure prescribed under Rule 25.
		(v) Unfitness on medical grounds	As per procedure prescribed under Rule 26.



1	2	3	4
		(vi) On own request	As per procedure prescribed under Rule 27.
Inspector General	Subordinate officers and sailors	(i) Misconduct	As per procedure prescribed under Rule 23.
		(ii) Unsuitability	As per procedure prescribed Under Rule 23.
		(iii) Unsatisfactory progress during training	As per procedure prescribed under Rule 24.
		(iv) Furnishing false/wrong information at the time of recruitment	As per procedure prescribed under Rule 25.
		(v) Unfitness on medical grounds	As per procedure prescribed under Rule 26.
		(vi) On own request	As per procedure prescribed under Rule 27.

22. Procedure for dismissal|removal of officers.—(1) When it is proposed to dismiss|remove an officer under section 11, he shall be given an opportunity to show cause in the manner specified in sub-rule (2) :

Provided that this sub-rule shall not apply —

- (a) Where the officer is dismissed|removed from the service on the grounds of misconduct which has led to his conviction by the criminal court.
- (b) Where the Central Government is satisfied that, for reasons to be recorded, it is not expedient or reasonably practicable to give the officer an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports of the officer's misconduct, the Director General is satisfied that the trial of the officer by a Coast Guard Court is not expedient or not practicable and is of the opinion that the further retention of the officer in the service is not desirable, the Director General shall so inform the officer together with all the reports adverse to him, and he shall be called upon to submit in writing his explanation and defence ;

Provided that the Director General may, with the prior approval of the Central Government, withhold from disclosure any such reports, or portion thereof, if its disclosure is not in the interest of the security of the State.

(3) In the event of the explanation of the officer being considered unsatisfactory by the Director General, or when so directed by the Central Government, the case shall be submitted to the Government with the officer's defence and the recommendations of the Director General as to the termination of officer's service in the manner specified in sub-rule (5) .

(4) Where, upon the conviction of an officer by a criminal court, the Central Government or the Director General considers that the conduct of the officer which has led to his conviction renders his further retention in the service undesirable, a certified copy of the judgement of the criminal court convicting him shall be submitted to the Central Government with the recommendations of the Director General as to termination of the officer's service in the manner specified in sub-rule (5) .

(5) When submitting a case to the Central Government under sub-rule (3) or (4), the Director General shall make his recommendation whether the officer's service should be terminated and if so, whether the officer should be

- (a) dismissed from the service ; or
- (b) removed from the service.

(6) The Central Government, after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgement of the criminal court, as the case may be, and the recommendation of the Director General, may dismiss or remove the officer from the service.

(7) When the Director General is satisfied that an officer is unfit to be retained in the service on the grounds of unsuitability, he may, after giving the officer an opportunity to explain his case, recommend to the Central Government that the officer's service be terminated. The Director General shall also forward to the Central Government the reasons for his recommendations and the record of service of the officer :

Provided that where in the interest of security of the State it would be inexpedient to give the officer an opportunity to explain his case, it shall be lawful for the Central Government to pass an order terminating the service of the officer without giving the officer an opportunity to explain his case.

(8) The Central Government on receipt of the report under sub-rule (7) may pass an order as it may deem fit for the dismissal or removal of the officer.

(9) The Central Government may in suitable cases retire or remove, the officer with or without pension or gratuity.

23. Procedure for dismissal|removal of enrolled persons.—(1) Where the Commanding Officer is satisfied that an enrolled person is considered unsuitable to be retained in the service on the grounds of misconduct or unsuitability, he may make a recommendation to the Inspector General in the Coast Guard Headquarters for the dismissal|removal of such person from the Coast Guard.

(2) In all cases of recommendation for dismissal or removal of a person, the Commanding Officer shall establish clearly the fact that the person has been given a suitable warning and sufficient time to improve. Documentary evidence to this effect shall accompany the recommendation.

(3) Where, upon the conviction of an enrolled person by a criminal court, the Deputy Inspector General under whom the person is serving considers that the conduct of the person which has led to his conviction renders his further retention in the service undesirable, a certified copy of the judgement of the criminal court convicting him shall be submitted to the Inspector General in the Coast Guard Headquarters with the recommendations of the Deputy Inspector General under whom the person is serving as to the termination of the person's service in the manner specified in sub-rule (4).

(4) The Inspector General in the Coast Guard Headquarters on receipt of a recommendation under sub-rule (1) or (3) may pass an order dismissing or removing the person concerned from the service.

(5) The Inspector General in the Coast Guard Headquarters may in suitable cases retire or remove the person with or without pension on gratuity.

24. Procedure for discharge|release on grounds of unsatisfactory progress in training.—(1) When it is proposed to discharge|release a member of the Coast Guard from the service on account of unsatisfactory progress in training, the Commanding Officer of training establishment, where the person is undergoing training, shall make a recommendation to the Central Government, or the Inspector General in the Coast Guard Headquarters as the case may be for the discharge or release of the person.

(2) In all cases of recommendations for discharge or release of a person, the Commanding Officer of the training establishment shall establish clearly the fact that the person has been given suitable warning and sufficient time to show progress, documentary evidence to this effect shall accompany the recommendation.

(3) The Central Government or as the case may be the Inspector General in the Coast Guard Headquarters on receipt of recommendation under sub-rule (1), may discharge or release the person concerned from the service.

25. Procedure for discharge|release on grounds of furnishing false|incorrect information at the time of recruitment.—The Central Government, or as the case may be, the Inspector General in the Coast Guard Headquarters may discharge or release a person subject to the Act on grounds of furnishing false|wrong information at the time of the recruitment of that person in the service. A show cause notice shall be issued to the individual before the person is discharge|released from the service.

26. Retirement|release|discharge on grounds of physical unfitness.—(1) When a person subject to the Act is found to be permanently unfit for the Coast Guard service by a Medical Board constituted under the Regulations for the Medical Services of the Armed Forces, he may be retired, released, or discharged from the service in accordance with the procedure laid down in this rule.

(2) The President of the Medical Board, shall immediately after the Medical Board has come to the conclusion that the person is permanently unfit for any form of Coast Guard service, issue a notice specifying the nature of the disease or disability he is suffering from and the finding of the Medical Board and also inform him that in view of the finding he may be retired, released or discharged from the service :

Provided that where in the opinion of the Medical Board the person is suffering from a mental disease and it is unsafe to communicate the nature of the disease or disability to the person, or the person is unfit to look after his interest, the nature of the disease or disability shall be communicated to the person's next of kin who shall have the right to petition under sub-rule (3).

(3) Such notice shall also specify that the person may within fifteen days of the date of receipt of the notice prefer a petition against the findings of the Medical Board to the President of the Medical Board.

(4) If no petition is preferred within the time specified in sub-rule (3), the person may be retired, released or discharged from the service, by an order to that effect made by the Central Government, in the case of officers, and by the Inspector General in the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled persons.

(5) If a petition is preferred within the time specified in sub-rule (3), the President, Medical Board shall refer it to an Appeal Medical Board, constituted under the Regulations for the Medical Services of the Armed Forces, for its decision on the petition. The findings of the Medical Board together with the records concerning the case shall be forwarded to the Director General in the Coast Guard Headquarters. In case there is no difference in the findings of the two Medical Boards, the person may be retired, released or discharged from the service, by an order to that effect made by the Central Government, in the case of officers, and by the Inspector General in the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled persons.

(6) In the case of a difference in the findings of the Medical Board and the Appeal Medical Board, the Director General in the case of officers, or the Inspector General in the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled persons, shall refer the matter to a Review Medical Board, constituted for the purpose under the Regulation for the Medical Services of the Armed Forces, for an opinion before retiring, releasing or discharging a person from the service on the ground of physical unfitness.

27. Procedure for discharge|release or retirement on own request.—(1) A member of the Coast Guard may, in exceptional cases, obtain his discharge, release or retirement from the service on extreme compassionate grounds, i.e. in cases where it is clear that undoubted material hardship will be caused to the member of the Coast Guard or his family members by his retention in the service.

(2) The Central Government may, having regard to the circumstances of any case, permit discharge, release or retirement of an officer from the service before attaining the age of retirement. The question

of discharge, release or retirement shall be a matter within the discretion of the Central Government.

(3) The Inspector General in the Coast Guard Headquarters may discharge, release or retire a member of the Coast Guard other than an officer on compassionate grounds.

(4) Application for discharge, release or retirement on compassionate grounds shall be forwarded by the Commanding Officer to the Inspector General in the Coast Guard Headquarters through the Regional Commander.

28. Date from which retirement|dismissal|removal| takes effect.—(1) The date of removal, resignation or discharge of a person subject to the Act shall take effect

from the date specified in that behalf in the order of retirement, dismissal, removal, resignation or discharge as the case may be.

(2) Retirement, dismissal, removal, resignation or discharge of a person subject to the Act shall not be retrospective.

## CHAPTER V

### PREScribed OFFICERS AND AUTHORITIES

29. Prescribed Officers and Authorities.—The officers and authorities mentioned in columns (3) and (4) of the Table below, shall be the prescribed officers and prescribed authorities under sections mentioned in column (1) for the purposes mentioned in column (2) of the said Table.

Section of the Act	Purpose	Prescribed officer	Prescribed authority
1	2	3	4
Section 8	To administer oath or affirmation.	Any officer	—
Section 9	For resignation and withdrawal from the post.	—	1. The Central Govt. for officers. 2. The Inspector General in the Coast Guard HQs for enrolled person.
Section 13(1)	For granting previous sanction to form association, etc., under clauses (a) (b) and (c) and of sub-section (1)	—	1. The Director General for officers. 2. The Inspector General in Coast Guard HQs for enrolled persons.
Section 63(1)	Appointment of Coast Guard Police officers.	Commanders, Regional Headquarters.	—
Section 71	To decide the choice of criminal court or Coast Guard Court for initiation of proceedings under the Act.	The Commanding officers under whose command the accused is serving.	—
Section 86(1)	To sign letters, returns or other documents.	The Director (Personnel) Coast Guard Headquarters and officer-in-charge, Bureau of Naviks.	—
Section 89	1. For taking steps for trial of a person of unsound mind. 2. Certificate of fitness to attend trial.	The officers who ordered original trial by the Coast Guard court. —	Medical Officer of the lunatic asylum or other place of safe custody where the person is kept.
Section 97	To order interim custody of a person sentenced to death.	The Commanding officer under whose command the accused person was serving.	—
Section 98	To give directions for execution of sentence to death.	The Commanding Officer under whose command the accused was serving.	—
Section 100 (1)	To give directions for confinement in a Civil prison.	The officer who ordered trial by the Coast Guard Court.	—
Section 100 (2)	To issue warrant for confinement of a person to a Civil prison.	The Executive Officer of the person under sentence.	—
Section 103	To issue warrant containing an order setting or varying any sentence to the officer in charge of a civil prison.	The Commanding Officer of the person under sentence.	—

30. For the purpose of section 57, the authorities mentioned in column (1) and holding ranks mentioned in column (2) shall have the power to award

punishment to the extent mentioned in column (3) of the Table below :

TABLE

Authority	Ranks	Extent to which punishment could be awarded.
(1)	(2)	(3)
1. The Commanding officer	All ranks	All punishments.
2. Executive Officer	(1) Commandant	(i) Musters of pay and allowances for first offence of leave breaking upto 48 hours to all enrolled persons. (ii) Extra work and drill for a period not exceeding 14 days to Naviks. (iii) Stoppage of leave for a period not exceeding 30 days to all enrolled persons. (iv) Admonition to all enrolled persons.
	(2) Deputy Commandant	(i) Musters of pay and allowances for the first offence of leave breaking upto 36 hours to all enrolled persons. (ii) Extra work and drill for a period not exceeding 7 days to Naviks. (iii) Stoppage of leave for a period not exceeding 15 days to all enrolled persons. (iv) Admonition to all enrolled persons.
	(3) Assistant Commandant	(i) Extra work and drill for a period not exceeding 7 days to Naviks. (ii) Stoppage of leave for a period not exceeding 15 days to other than subordinate officers. (iii) Admonition to persons other than subordinate officers.
3. Officers of the Watch/Officer of the Day.	Assistant Commandant and above.	(i) Extra work and drill for 1 day to Naviks. (ii) Admonition to Naviks.

31. Oath or affirmation.—Every member of the Coast Guard shall make and subscribed an oath or affirmation in the following form :—

#### FORM OF OATH/AFFIRMATION

I, A.B. do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will as in duty bound, honestly and faithfully serve with Coast Guard wherever ordered, by air, land or sea and that I will observe all commands of the President of the Union of India and Commands of any officer set over me even to the peril of my life.

Signature—

Counter-signature—

(Name and designation of person administering oath).

#### CHAPTER VI

#### COMPLAINTS AND REPRESENTATIONS

32. Complaints to higher authorities.—(1) If an officer or an enrolled person thinks that he has suffered any personal oppression, injustice, or other ill treatment or that he has been treated unjustly in any way or wishes to make a representation affecting

his welfare or has any suggestion to make in connection with service, he shall bring it to the notice of his superior officer.

(2) It shall be the duty of the superior officer to whom a representation has been given, to forward the same to the higher authorities for appropriate action.

(3) Any other method of seeking redressal from the superior officer/authority save those mentioned in these rules is forbidden.

33. To whom complaint shall be made.—(1) If the complainant is a Commanding Officer of the Coast Guard Ship, his complaint shall be in writing and shall be addressed to his immediate superior officer.

(2) If the complainant is an officer serving in one of the Coast Guard Ships his complaint shall be made orally to the Commanding Officer whereby a complainant is to make an oral request to see the Commanding Officer for that purpose. If the complainant is an officer, such request shall be made through the Executive Officer and if the complainant is a head of the department, a request shall be made direct to the Commanding Officer. If the complainant is an officer working in a particular department, the request shall be made in the first place to the head of the department.



(3) If the complainant is an enrolled person, his complaint shall be made orally to the Commanding Officer. A request to see the Commanding Officer shall be made to the Executive Officer through the complainant's Divisional or Departmental Officer. An enrolled person detached from his ship or his establishment shall make his complaint to the officer in whose command he may be at that time.

34. Rules to be observed by the complainant.—(1) The complaint shall be confined to statement of facts on which the complaint is based and to the alleged consequences to the complainant himself.

(2) Joint complaints by two or more persons are not allowed. Each individual shall make his own complaint.

(3) It shall be the duty of the person making a complaint, either oral or written, to ensure that,—

(a) the statement of facts in the complaint is true to the best of his knowledge; and

(b) the complaint is not made in a language which is disrespectful, insubordinate or subversive to discipline.

35. How the complaint shall be dealt with.—(1) On receipt of any complaint the Commanding Officer, or other officer, receiving the same shall satisfy himself that the complaint is made in accordance with these rules. He shall then deal with it in the exercise of his discretion as may seem to him right and cause the complainant to be informed of his decision.

(2) If the Commanding Officer or the other officer receiving complaint refuses or is unable to remedy the complaint so made, the complainant may respectfully ask that he may be allowed to make his complaint in writing. On receiving such request, the Commanding Officer, or the other officer, shall give the complainant 24 hours to reconsider the matter. The complainant may then address his complaint in writing to the Commanding Officer, or the other officer, who shall then forward the complaint to the next superior officer together with his remarks thereon.

(3) If the complainant is not satisfied with the decision on his complaint or if he does not get the redress asked for within a period of one month from the date of submission of his complaint or the date of its despatch to the next superior authority, as the case may be, he may request that his complaint be forwarded to the next superior authority and so on to the Director General or the Central Government, as the case may be, and all such requests shall be complied with. The complaint shall be justified in appealing direct to the next superior authority if he does not receive a final reply within a period of six months from the date of submission of his complaint.

## CHAPTER VII

### BOARD OF INQUIRY

36. Convening of Board of Inquiry.—A Board of Inquiry may be convened by the Director General or by Commanders of Regional Headquarters whenever any matter arises upon which the said authority requires to be thoroughly informed.

37. Constitution of Board of Inquiry.—A Board shall consist of an officer as Presiding Officer and at least two members who shall be either officers or subordinate officers or both. Persons not subject to the Act may be also appointed as member when the Board is to investigate matters of a specialised nature and officers subject to the Act with the requisite qualifications are not available.

38. Duties of the Board.—(1) Board shall perform such duties as may be directed by the authority convening the Board.

(2) Such directions shall always be made in writing and may in case of urgency be conveyed by signal. However, the order convening the Board shall be made in the format given in the Annexure.

39. Procedure for Board of Inquiry.—(1) The Board shall be guided by the provisions of these rules and also by the Coast Guard Orders, for the time being in force, and the written instructions of the convening authority; provided that the Coast Guard Orders and the written instructions are not inconsistent with the provisions of these rules.

(2) The proceedings of the Board of Inquiry shall not be open to the public. Only such persons may attend the proceedings as are permitted by the Board to do so.

(3) Every witness examined by the Board shall be informed in the following terms which shall be recorded in the minutes :—

“You are privileged to refuse to answer any question, the answer to which may tend to expose you to any penalty or forfeiture. It will be for you to raise the objection and for the Board to decide whether you must answer the question or not.”

(4) Whenever an enquiry affects the character or reputation of a person serving in the Coast Guard or may result in the imputation of liability or responsibility for any loss or damage, or is made for the contravention of any rules or general or local orders, full opportunity shall be afforded to such person for being present throughout the enquiry and of making any statement and of giving any evidence he may wish to make or give, and of cross-examining any witness whose evidence in his opinion affects him, and producing any witness in his defence. The Presiding Officer of the Board shall take such steps as may be necessary to ensure that any such person so affected and not previously notified receives notice of, and fully understands, his rights under these rules.

(5) The proceedings of the Board shall be recorded in accordance with any directions contained in the Coast Guard Orders for the time being in force and any instructions given by the convening authority. The minutes of such proceedings shall contain a verbatim report of all the evidence given, and all questions and answers shall be numbered in one series throughout the minutes.

(6) The proceedings of the Board or any confession, statement, or answer to a question made or given before the Board, shall not be admissible in



evidence against a person subject to the laws relating to any Armed Forces of the Union nor shall any evidence respecting the proceedings of the Board be given against any such person. Provided that nothing in these rules shall prevent proceedings from being used for the purpose of cross-examining any witness.

40. Board of Inquiry when to be held.—(1) A Board of Inquiry may be convened to investigate into any matter of importance such as,—

- (a) loss, stranding or hazarding of Coast Guard Ships, Vessels, or Air Craft ;
- (b) accidental death of, or serious bodily injury to, any person on board a ship|Establishment|Air Craft ;
- (c) loss of classified books or publication involving breach of security ;
- (d) damage to or loss of Government property or stores, or loss of public money ;
- (e) damage to private persons or property, in respect of which there is likely to be a claim against the Central Government or the Coast Guard.

41. Action on the proceedings of Board of Inquiry.—The proceedings of the Board of Inquiry shall be submitted by the Presiding Officer of the Board to the convening authority. On receipt of the proceedings the convening authority shall—

- (i) take such action as is within its jurisdiction and as it may deem fit to take ;
- (ii) submit the same together with its comments thereon to the higher authority, if required to do so under the orders of such authority.

42. Copies of the proceedings of the Board.—The following persons shall be entitled to receive a copy of the proceedings of the Board :—

- (a) Any person subject to the Act who is tried by a Coast Guard Court in respect of any matter or thing which has been reported by the Board ; or
- (b) Any person in Government service whose character, conduct or reputation is, in the opinion of the Director General, affected by anything in the evidence before the Board, unless the Director General sees reason to order otherwise.

Explanation : For the purpose of these rules proceedings shall include findings of the Board but shall not include recommendations of the Board.

## CHAPTER VIII

### APPLICATIONS AND PETITIONS

43. Application and Petitions against findings and sentence of a Coast Guard Court.—(1) A person subject to the Act, who has been tried by a Coast Guard Court, may make an application to the Chief

Law Officer for review of the proceedings of the Coast Guard Court under section 117 of the Act.

(2) A petition shall also be allowed to be made to any authority mentioned in section 119 of the Act.

44. Period of Limitation.—An application for judicial review shall be submitted within 21 days of the date on which the sentence was passed by the Coast Guard Court. A petition under section 119 shall be submitted within three months of the date of the order of the Director General on the Judicial Review by the Chief Law Officer of the proceedings of the trial by the Coast Guard Court ;

Provided that the time taken by such person to obtain a copy of the proceedings or the orders of the Director General on the Judicial Review of the proceedings by the Chief Law Officer shall be excluded in calculating the period of 21 days or 3 months as the case may be :

Provided further that an application received after the expiration of the aforesaid period may be entertained by the Director General or the Central Government as the case may be if he or it is satisfied that the delay was due to reasons beyond the control of the applicant.

45. Mode of submitting application and petition.—

(1) An application or a petition may be presented in person or sent by a registered post. It shall be in duplicate and shall be signed by the applicant. It shall state succinctly and clearly all grounds on which the conviction or sentence is sought to be impugned. The applicant should also state whether he desires to be heard in person or through a legal practitioner or an officer of the Coast Guard if the application is under Section 117 of the Act. No personal hearing is required to be given if the petition is under Section 119 of the Act.

(2) An application under Section 117 is to be submitted directly to the Chief Law Officer. A petition under section 119 is to be submitted through the Commander Coast Guard Region in whose command the trial was held. The Commander Coast Guard Region shall forward it to the Director General with his remarks within a period of one month.

(3) A petition against summary award of punishment shall not be entertained. If there are exceptional circumstances warranting interference with the finding or sentence awarded summarily, the case is to be forwarded to the Coast Guard Headquarters through proper channel with full details necessitating the exercise of plenary powers of the Director General or the Central Government as the case may be. As in the case of a petition under section 119 of the Act, the period of limitation shall be 3 months from the date on which the summary punishment was awarded.

[CGHQ No. LW/0216]

T. K. BANERJI, Jt. Secy. (Navy)

M of D.I.D. No. LW/0216/746[D(N-III)]86, dated 2-5-1986.

Annexure

(Rule 38)

FROM  
AT  
DATE  
TO

## ORDER FOR BOARD OF INQUIRY

You are hereby required to assemble in \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_, the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ as a board of inquiry whereon \_\_\_\_\_ is to be Presiding Officer, and to hold a full and careful investigation into the circumstance of \_\_\_\_\_.

2. Your report is to be accompanied by the minutes of the evidence taken verbatim and is to contain an expression of your opinion on the merits of the case as disclosed by the evidence; it is also to state fully to whom, if to any person, blame is attributable and to what extent.

3. The questions in the minutes are to be numbered in one series throughout, and the minutes as well as the report, are to be signed by the Presiding Officer and Members of the Board. The name of the witness under examination is to be noted at the head of each page of the report and minutes are to be furnished.

4. Before submitting the minutes and report, you are to see that all papers (or copies of them, if originals are not available) referred to in the proceedings of the Board accompany the original and all copies of the minutes, and that the rules regarding the preparation and submission of the minutes have been fully complied with.

5. Any other matter which arises from the proceedings and which the Board considers shall be brought to the notice of convening officer is to be made the subject of a separate report.

6. You are to be guided by provisions of Chapter VII of the Coast Guard (General) Rules, 1986.

7. \_\_\_\_\_ is to arrange for the attendance of such witnesses as may be required to be examined by the board.

8. \_\_\_\_\_ is to arrange for the presence during the inquiry of a confidential stenographer and for provisions of the necessary stationery.

9. All relevant papers are herewith handed to the Presiding Officer of the Board who is to return them with the minutes in due courses.

Signature of convening Officer